वस्त्र निगम लि० की एक सहायक कम्पनी है का औद्योगिक विकास (विनियमन) अधिनियम के अधीन जून, 1971 में अधिग्रहण किया गया था तथा जिसका बाद में 1-4-74 से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था । चूंकि यह एक रुग्ण एकक था तथा इसमें पहले से चली आ रही कुछ असमर्थताओं के कारण इसे बराबर हानि उठानी पड़ी है । इन में से कुछ कारण पुरानी और टूटी मशीनों का होना ब्याज का भारी बोझ होना, श्रमिकों का अनुपात अधिक होना और श्रमिकों में चली आ रही अनुशासन हीनता है जिस के फलस्वरूप उत्पादकता में कमी हुई है । इस एकक में वर्ष 1976-77 में 94.58 लाख रुपये की हानि हुई है । इन हानियों को रोकने के लिये राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा अनेक अभ्युपाय किये जा रहे हैं । इनमें आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वित करना, लाभकर किस्मों का धीरे-धीरे लागू किया जाना, कच्ची सामग्री का परीक्षण करने के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव, लागत लेखा नियंत्रण लागू करना आदि सम्मिलित हैं । इसे एक जीव्य एकक बनाने के लिए अर्थोपाय सुधारने के लिए हाल ही में मिल का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण भी किया गया है । सर्वेक्षण दल की सिफारिशों का राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा अध्ययन किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). कपड़ा मजदूर एकता यूनियन से भंडार खरीद सम्बन्धी कुछ कमियों और महाप्रबन्धक की नीतियों के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं इन शिकायतों की अभी जांच की जा रही है । जांच पूरी हो जाने पर उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी ।

भारतीय सीमेंट निगम द्वारा बस्तर जिले में एक सीमेंट कारखाने की स्थापना

3981. **श्री गोविन्दराम भिरी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय सीमेंट निगम बस्तर जिले में एक सीमेंट कारखाने की स्थापना कब करेगी और उसमें कब से उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) : भारतीय सीमेंट निगम का मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में सीमेंट संयंत्र लगाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

कोयला खानों पर राजस्व की बकाया राशि

3982. **श्री गोविन्दराम भिरी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप गैर-कोकिंग कोयला खानों के भूतपूर्व मालिकों और केन्द्रीय सरकार के बीच खनिज सम्बन्धी सरकारी राजस्व की बड़ी राशि विवादग्रस्त है और क्या यह अभी भी उन पर बकाया है ; और

(ख) मुआवजा निपटान आयुक्त, कोयला खान, कलकत्ता के न्यायालय में इस समय लम्बित मामलों में क्या प्रगति हो रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) राज्य सरकारों ने राष्ट्रीयकरण की तारीख को पिछले कोयला खान मालिकों से प्राप्य रायल्टी की बकाया राशि के लिए भुगतान आयुक्त के पास दावे दाखिल किए हैं परन्तु पिछले मालिकों और केन्द्रीय सरकार के बीच कोई विवाद नहीं है ।

(ख) भुगतान आयुक्त, कलकत्ता के पास दाखिल किए गए कुल 47,631 दावों में से नवम्बर, 1977 तक 15,202 दावे अस्वीकार/अन्ततः विचारार्थ स्वीकार कर लिये गये हैं । अन्य मामले विचार की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।